of identified irrigation projects and distribution of vegetable minikits to farmers for 1987-88 respectively.

**Approval of the modified National Oilseeds Development Prject**

814. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had recently approved the modified National Oilseeds Development Project (NODP) for the remaining period of the current plan period;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of the areas where this project will be implemented; and

(d) to what extent the import of oilseeds will be minimised and the indigenous production is likely to be boosted?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) The National Oilseeds Development Project for the first year of 1985-86 is modified and is being implemented in 17 oilseeds growing States from 1986-87, and will be continued as such during the remaining period of Seventh Plan Under this project, financial assistance is given on various critical inputs like multiplication and supply of improved seeds, provision for plant protection measures, improved farm implements supply, organising large sized block demonstrations etc.

(c) The Project is in operation in 17 important oilseeds growing States.

(d) Government of India is taking every possible step to boost the production of oilseeds with the implementation of National Oilseeds Development Project, Oilseeds Production Thrust Project and constitution of Oilseeds Technology Mission in order to minimise the import of edible oil and to achieve self-sufficiency.

**उत्तर प्रदेश को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष सहायता**

815 **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** . क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित ग्रामों मे पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश को क्या बिशेष सहायता प्रदान की गई है ,

(ख) क्या सरकार आदिवासी ग्रामों तथा पहाडी ग्रामों की ओर, जहा पानी की अत्यधिक कमी है, विशेष ध्यान देने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय मे ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के *उन ग्रामीण* क्षेत्रो के लिए "वेज एण्ड मीन्स एडवांस" के रूप में 7.5 करोड़ रुपए की तदर्थ सहायता रिलीज की थी जो पीने के पानी की कमी से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए है । इसके अलावा, रिग मशीनें तथा अन्य उपकरण खरीदने के लिए 53.0 लाख रुपए भी रिलीज किए गए थे । हाल ही मे, केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो मे पीने के पानी की सप्लाई के लिए उपर्युक्त सहायता सहित सूखा राहत के अन्तर्गत अधिकतम व्यय सीमा के अधीन 9.23 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को रिलीज की गई तदर्थ सहायता पानी की कमी वाले सभी क्षेत्रो के लिए है जिनमे पानी की अत्यधिक कमी व ले आदिवासी गांव तथा पर्वतीय गाव भी शामिल है ।

**उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रामीण श्रमिकों के लिए कार्यक्रम**

816. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) *क्या* उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण श्रमिकों के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 और 1987-88 के बजटों में रखी गयी विशेष अनुदान राशि में से ग्रामीण श्रमिकों के लिये कितनी राशि का आवंटन किया गया है, और

(ग) इन दोनों प्रदेशों में इससे क्रमशः कितने-कितने लोग लाभान्वित हुए हैं अथवा कितने-कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)**: (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत संबंधी निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए सहायता मांगी है। केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट तथा राहत कार्यों सबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए, व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा की व्यवस्था की गई है:—

| | (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| 1986-87 | 3.45 |
| 1987-88 | 100.62 |

बाढ़ राहत के अंतर्गत राज्य सरकारों को रोजगार सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए स्थिति की गंभीरता और रोजगार की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती है।

बिहार सरकार ने इन वर्षों में पड़े सूखे से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए कोई अनुरोध/ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

**चावल उत्पादन के लिए नई तथा सस्ती तकनीक**

817. **श्रीमती रेणुका चौधरी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा हाल में चावल के उत्पादन के लिये एक नई तथा सस्ती तकनीक विकसित किये जाने के दावे की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस दावे की वास्तविकता की जांच परख की है, यदि हां, तो इस तरह की गई जांच के निष्कर्ष क्या है?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)** (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) बताई गई तकनीक में एक विदेशी फलीदार हरी खाद के पौधे **सैस्बेनिया रोस्ट्राटा** को खेत में उगाना और चावल उगाने से पहले इसको जोत देना शामिल है। जड़ों में अधिक प्रभावी ग्रंथियां बढ़ाने हेतु इस पौधे के बीजों को **राइजोबियम** जीवाणु कल्चर से टीका लगाया जाता है। **सैस्बेनिया** की प्रजातियों के विपरीत, इस विशेष प्रजाति में तनों पर भी नत्रजन निर्धारण ग्रंथियों को उत्पन्न करने की क्षमता है। **सैस्बेनिया रोस्ट्राटा** एक विदेशी पौधा है जिसका इस देश में उत्पन्न करना शुरू किया जा रहा है। इस पौधे की देश के विभिन्न चावल उत्पादक क्षेत्रों में हरी खाद के रूप में अनुकूलता, इसकी नत्रजन निर्धारण हेतु क्षमता और चावल की फसल के लिए नत्रजन की अनुपूरकता की जांच की जा रही है।

**Supply of Rapeseed oil to West Bengal**

818. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what has been the quantity of rapeseed oil supplied to West Bengal in August, September and October during the current year by the Central Government;

(b) whether it is a fact that there has been decline in the supply; and

(c) if so, the reasons therefor?